भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2223

उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा

†2223. **श्री अजय कुमार मंडल:**

श्री के. गोपीनाथ:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से भागलपुर सहित बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के लिए स्मार्ट बोर्ड और एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा जैसी अवसंरचना विकसित करने तथा ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए कितनी बजट राशि आवंटित की गई है;

(घ) सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या है;

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट कक्षाएं शुरू करने में सरकार के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या यह सच है कि देश के सुदूर भागों के कई विद्यालयों में विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान कराने के लिए प्रौद्योगिकी का अभी भी प्रसार होना बाकी है, यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा लागू कर रही है, जो प्री-स्कूल से कक्षा XII तक विस्तारित स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य भागलपुर, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षणों के संचालन, अनुकूल शिक्षण परिवेश प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल

अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, आईसीटी और डिजिटल पहलों के लिए सहायता, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण आदि जैसी विभिन्न पहलों के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी और डिजिटल पहल घटक को पारंपरिक अनुदेशात्मक शिक्षक-केंद्रित प्रयास से शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को रूपांतरित करने के लिए शुरू किया गया है। इस घटक में कक्षा VI से XII तक को कवर किया गया है।

इस संबंध में प्रावधान निम्नानुसार हैं:

क. बजटीय प्रावधान

स्कूलों के लिए 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित दो विकल्पों के लिए उपलब्ध है:

विकल्प I: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे अपनी मांग और आवश्यकता के अनुसार आईसीटी या स्मार्ट शिक्षण-कक्ष का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले में, एक अतिरिक्त आईसीटी लैब पर भी विचार किया जा सकता है।

विकल्प II: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठाया है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट शिक्षण-कक्ष का लाभ उठा सकते हैं।

ख. वित्तीय प्रावधान

आईसीटी लैब: 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति स्कूल 6.40 लाख रुपये तक का गैर-आवर्ती अनुदान और प्रति स्कूल प्रति वर्ष 2.40 लाख रुपये तक का आवर्ती अनुदान।

स्मार्ट शिक्षण-कक्ष: स्मार्ट शिक्षण-कक्ष के लिए गैर-आवर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये है और आवर्ती अनुदान 0.38 लाख रुपये है।

बिहार राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य में 6,406 प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों को आईसीटी लैब से सुसज्जित किया गया है, जिसमें भागलपुर जिले के 215 विद्यालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य भर में 2,710 प्रारंभिक विद्यालयों को स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से कवर किया गया है, जिनमें से 96 भागलपुर जिले में हैं।

समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वित्तीय स्वीकृति **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ) से (च): देश भर के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने के लिए, पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है जो शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। इस पहल में निम्नलिखित शामिल हैं:

- दीक्षा (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए राष्ट्र का डिजिटल बुनियादी ढांचा है। इस प्लेटफॉर्म पर सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोड वाली एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं।

- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट- शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग।

- दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेज़ी) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विशेष ई-सामग्री विकसित की गई है।

- डीटीएच टीवी चैनल- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार, 12 डीटीएच चैनलों को बढ़ाकर 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल कर दिया गया है ताकि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। चैनल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित कर दिए गए हैं और प्रचालन में हैं।

*****

अनुलग्नक

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के संबंध में माननीय संसद सदस्य, श्री अजय कुमार मंडल और श्री के. गोपीनाथ द्वारा 5 अगस्त 2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2223 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2024-25 तक समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्मार्ट शिक्षण-कक्ष और आईसीटी लैब के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय स्वीकृति का विवरण

राज्य का नाम	वित्तीय अनुमोदन रुपये)लाख में(	
	आईसीटी लैब	स्मार्ट शिक्षण कक्ष*

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	405.3	0
आंध्र प्रदेश	20676.1	12456
अरुणाचल प्रदेश	1478.773	454.8
असम	22099.2	15398.4
बिहार	7699.2	11630.4
चंडीगढ़	254.1	352.8
छत्तीसगढ़	8706.8	24763.2
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	355.55	376.4
दिल्ली	44.8	3850.31
डीएनडी-डीएनएच	219.8	7655.6
गोवा	40.4	0
गुजरात	4940.9	1096.8
हरियाणा	6160.5	16799.22
हिमाचल प्रदेश	7460.3	8287.31
जम्मू और कश्मीर	11452.42	9268.8
झारखंड	25256.7	4828.8
कर्नाटक	10869.5	2356.8
केरल	0	5031
लद्दाख	694.4	1305.6
लक्षद्वीप	182.2	103.2
मध्य प्रदेश	11738.5	18552
महाराष्ट्र	8201.8	8402.4
मणिपुर	2548.79	1305.6
मेघालय	1562.5	191.84
मिजोरम	2023.418	571.2
नगालैंड	137.97	2347.4
ओडिशा	14828.8	17606.4
पुदुचेरी	294.4	348
पंजाब	10082.6	9600
राजस्थान	14943.89	19746
सिक्किम	1033.75	776.8
तमिलनाडु	45706.5	16905.6
तेलंगाना	4968	9556.8
त्रिपुरा	4844.9	2126.4
उत्तर प्रदेश	26529.21	64862.4
उत्तराखंड	1536	8912.599
पश्चिम बंगाल	9062.4	820.8
कुल	**289040.4**	**301094.9**

स्रोत: प्रबंध *2020-21 में समग्र शिक्षा में शुरु किया गया स्मार्ट शिक्षण-कक्ष का प्रावधान।